MODEL ANSWER

Q. The Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) reforms of 1991 marked a paradigm shift in India's economic policy, spearheaded by leaders like Dr. Manmohan Singh. Critically analyze the impact of these reforms on India's economic growth, social equity, and global positioning.

The Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) reforms of 1991, spearheaded by Dr. Manmohan Singh as the then Finance Minister, marked a pivotal moment in India's economic history. Triggered by a severe economic crisis, these reforms aimed to dismantle restrictive controls, reduce state dominance, and integrate India with the global economy. While they spurred economic growth, they also raised concerns about equity and sustainability.

Impact of LPG Reforms

Economic Growth

- **Enhanced GDP Growth**: India's GDP grew from $270 billion in 1991 to $2.9 trillion by 2020, with an average growth rate of 7% per annum. Dr. Manmohan Singh's policies laid the foundation for this transformation by emphasizing fiscal discipline and structural adjustments.
- **Foreign Investments**: FDI inflows increased from $97 million in 1991 to $82 billion in 2020-21, boosting infrastructure and industrial sectors.
- **Industrial Development**: The dismantling of the License Raj enabled exponential growth in sectors like IT, telecom, and automobiles.

Social Equity

- **Poverty Reduction**: Poverty rates declined from 45% in 1993-94 to 22% in 2011-12.
- **Employment Generation**: Job creation improved, but 88% of the workforce remains in the informal sector, reflecting limited formal employment opportunities.
- **Income Inequality**: Rising disparities highlighted the unequal distribution of reform benefits, with urban areas outpacing rural ones.

Global Positioning

- **Trade Integration**: India's share in global trade increased from 0.5% in 1991 to around 2% in 2022, showcasing improved competitiveness.
- **Economic Growth:** India is currently the fifth-largest economy in the world, with a GDP of $3.89 trillion at current prices, growing at an impressive rate of 8.2 per cent in FY23-24.
- **Economic Diplomacy**: The reforms, guided by Dr. Singh's strategic vision, positioned India as an emerging global economic power and a preferred investment destination.

While transformative, the LPG reforms also brought challenges. Jobless growth emerged as a concern, with economic expansion failing to create sufficient formal employment. Regional disparities widened, benefiting urban and industrial hubs more than rural areas. Income inequality increased, deepening the wealth gap. Additionally, rapid industrialization and urbanization led to significant environmental degradation.

Thus, the LPG reforms, with Dr. Manmohan Singh at their helm, transformed India into a rapidly growing economy with enhanced global integration. However, challenges like jobless growth, income inequality, and environmental degradation underscore the need for policies that ensure inclusive and sustainable growth while balancing economic expansion with equity and environmental protection.

प्रश्न. 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया, जिसका नेतृत्व डॉ. मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने किया। भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और वैश्विक स्थिति पर इन सुधारों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधारों ने, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। एक गंभीर आर्थिक संकट के बीच, इन सुधारों का उद्देश्य प्रतिबंधात्मक नियंत्रणों को खत्म करना, राज्य के प्रभुत्व को कम करना और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना था। जबकि इन सुधारों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, इनसे संबंधित समानता और स्थिरता को लेकर चुनौतियाँ भी सामने आईं।

<u>एलपीजी सुधारों का प्रभाव</u>

आर्थिक विकास

- **जीडीपी में वृद्धि:** भारत की जीडीपी 1991 में 270 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 तक 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जिसकी औसत वृद्धि दर 7% प्रति वर्ष रही। डॉ. मनमोहन सिंह की नीतियों ने राजकोषीय अनुशासन और संरचनात्मक समायोजन पर जोर देकर इस परिवर्तन की नींव रखी।
- **विदेशी निवेश:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 1991 में 97 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 82 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला।
- **औद्योगिक विकास:** लाइसेंस राज के खत्म होने से आईटी, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई।

सामाजिक समानता

- **गरीबी दर में कमी:** गरीबी दर 1993-94 में 45% से घटकर 2011-12 में 22% हो गई।
- **रोजगार सृजन:** रोजगार सृजन में सुधार हुआ, लेकिन लगभग 88% कार्यबल अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में बना हुआ है, जो सीमित औपचारिक रोजगार अवसरों को दर्शाता है।
- **आय की असमानता:** बढ़ती असमानताओं ने सुधार लाभों के असमान वितरण को उजागर किया, जिसमें शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से आगे निकल गए।

वैश्विक स्थिति

- **व्यापार का एकीकरण:** वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 में 0.5% से बढ़कर 2022 में लगभग 2% हो गई, जो बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- **आर्थिक विकास:** भारत वर्तमान में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी मौजूदा कीमतों पर $3.89 ट्रिलियन है, जो वित्त वर्ष 23-24 में 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से बढ़ रही है।
- **आर्थिक कूटनीति**: डॉ. सिंह की रणनीतिक दृष्टि से निर्देशित सुधारों ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति और एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया।

परिवर्तनकारी होने के साथ-साथ, एलपीजी सुधार चुनौतियाँ भी लेकर आए। बेरोज़गारी वृद्धि एक चिंता का विषय बन गई, क्योंकि आर्थिक विस्तार पर्याप्त औपचारिक रोज़गार उत्पन्न करने में विफल रहा। क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ीं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी और औद्योगिक केंद्रों को अधिक लाभ हुआ। आय असमानता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने पर्यावरणीय क्षरण को जन्म दिया।

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी सुधारों ने भारत को वैश्विक एकीकरण के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदल दिया। हालांकि, बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी, आय असमानता और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियाँ ऐसी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं जो आर्थिक विस्तार को समानता और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करें।